



वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने [वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद \(Financial Stability and Development Council-FSDC\)](#) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिये प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार तथा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर जोर दिया।
- यह नोट किया गया कि सरकार और नियामकों द्वारा वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों, वित्तीय स्थितियों तथा बाजार के विकास की निरंतर आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी भेद्यता को कम करने एवं वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिये उचित और समय पर कार्रवाई की जा सके।
- परिषद ने [वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता](#) के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में तैयारी पर ध्यान दिया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC):

- स्थापना:**
 - यह वित्त मंत्रालय के तहत एक **गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद** है तथा इसकी स्थापना **वर्ष 2010** में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी।
 - FSDC की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित **रघुराम राजन समिति (2008)** द्वारा किया गया था।
- संरचना:**
 - इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों **RBI, SEBI, PFRDA** और **IRDA** के **प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS)** के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
 - वर्ष 2018 में सरकार ने **आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के ज़िम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दवाला एवं दवालियापन बोर्ड (IBBI)** के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से FSDC का पुनर्गठन किया।
 - FSDC उप-समितिकी अध्यक्षता **RBI के गवर्नर** द्वारा की जाती है।
 - आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद **विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।**
- कार्य:**
 - वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय बढ़ाने** और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रक्रिया को मजबूत एवं संस्थागत बनाना।
 - अर्थव्यवस्था के वृहद-विकल्पपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना।** यह बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council) के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह नीति आयोग का एक अंग है
- संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है।
- यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/financial-stability-and-development-council-1>

